



अर्जेटीना और राष्ट्रपति मौरिसियो मैक्री

डॉ. स्तुति बनर्जी

राष्ट्रपति मौरिसियो मैक्री ने दिसंबर 2015 में अर्जेटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार, श्री डैनियल साइनोली पर उनकी जीत से, राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज किर्चनर के नेतृत्व में पेरोनिस्ट पार्टी के बारह वर्ष के राष्ट्रपतित्व की समाप्ति हुई। राष्ट्रपति बनने के इस अभियान में, श्री मैक्री, रैंडिकल सिविल यूनियन और लिबरल सिविल को लिशन के साथ अपनी मैक्री प्रोपुएस्टा रिपब्लिकन पार्टी (पीआरओ) को एकजुट करने में सक्षम रहे थे। राष्ट्रपति मैक्री का चुनाव अभियान, "लेट अस चेंज: चेंज इज पॉसिबल", अर्जेटीना के मतदाताओं में गूंजता रहा है। मुख्य रूप से घरेलू जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उनके अभियान में उन चार चुनौतियों की पहचान की गई, जिन पर नए राष्ट्रपति का विशेष ध्यान रहेगा। वे थीं क) शून्य गरीबी प्राप्त करना, ख) देश को उत्तरी प्रांतों के साथ जोड़ने के लिए एक बुनियादी ढांचा परियोजना, ग) नशीली दवाओं के व्यापार को समाप्त कर, अर्जेटीना की भावी पीढ़ी को बचाना घ) और अंत में, यह सुनिश्चित करना कि सरकार लोगों के लिए पारदर्शी और जवाबदेह है। अर्जेटीना की विदेश नीति पर उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के साथ बिगड़े संबंधों पर निर्माण करते हुए क्षेत्रीय संस्थानों का निर्माण करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

उनकी सरकार के अर्जेटीना की राष्ट्रीय कांग्रेस में अल्पसंख्यक जा होने के बावजूद राष्ट्रपति मैक्री अपना पदभार संभालने के बाद, डेढ़ वर्ष में अपने सुधार के एजेंडे को लागू करने में सक्षम रहे हैं।¹ दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त किर्चनरवाद के विपरीत, नई गठबंधन सरकार - कैबिमोस - चुनावों के बाद दोनों सदनों में अल्पमत में थी। नई सरकार की सफलता की कुंजी इस तथ्य को माना जा रहा है कि राष्ट्रपति मैक्री प्रांतीय नेताओं और राज्यपालों के साथ अपने संबंध विकसित करने में सक्षम रहे हैं। राज्यपालों का विशेष महत्व है, क्योंकि अर्जेटीना निर्वाचन प्रणाली राज्यपालों को अपने प्रांतों से चुने गए संघीय सांसदों पर काफी प्रभाव रखने की अनुमति देती है। साथ ही, राज्यपालों पर राष्ट्रपति के प्रभाव को देखते हुए, प्रांत राष्ट्रीय सरकार से राजकोषीय हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भर हैं। इससे राष्ट्रपति मैक्री को कांग्रेस के भीतर अपनी नीतियों के लिए समर्थन इकट्ठा करने का अवसर मिला है।² राष्ट्रपति ने अपने सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग किया है।

आर्थिक सुधार

अर्जेटीना सरकार अपने संप्रभु ऋण पर अर्जेटीना की चूक के चक्र को समाप्त करने में सक्षम रही है। 2015 में यह अपने चार मुख्य अमेरिकी लेनदारों के साथ एक समझौते पर पहुंचने में सक्षम रही। अर्जेटीना को लेनदारों द्वारा की जा रही 4.65 अरब अमेरिकी डॉलर की मांग की तुलना में 25% कम भुगतान करना होगा, लेकिन यह उन निवेशकों के लिए बहुत अधिक होगा, जिन्होंने इसके अंकित मूल्य के एक अंश पर

ऋण खरीदा था। अर्जेंटीना 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लिए डिफॉल्ट संप्रभु बॉन्ड रखने वाले अतिरिक्त 115 व्यक्तिगत लेनदारों के साथ निपटारा किया। इसने डिफॉल्ट वाले बांडों के धारक इतालवी निवेशकों के साथ 1.35 अरब डॉलर के समझौता किया और अमेरिकी अदालतों में 9 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के दावों का निपटान करने के लिए 6.5 अरब डॉलर खर्च करने की प्रतिबद्धता स्वीकार की।³ इन समझौतों के साथ, अर्जेंटीना ने लेनदारों के साथ समझौता किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश के अलगाव को समाप्त करने में मदद की।

अपने अन्य आर्थिक सुधारों में, राष्ट्रपति मैक्री ने गेहूं, गोमांस और मक्का जैसे कृषि उत्पादों पर शुल्क को कम कर दिया और अर्जेंटीना के सबसे बड़े निर्यात सोया पर शुल्क को 35% से घटाकर 30% कर दिया। सरकार ने बहुत जरूरी विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था का अनुकरण करने के लिए, जमा किए हुए अनाज के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अमेरिकी डॉलर के विनिमय पर लगा ये गये नियंत्रण को भी हटा दिया। मुद्रा नियंत्रण का उठाना यह भी सुनिश्चित करता है कि मौजूद कई दरों की बजाय केवल एक विनिमय दर होगी। नवंबर 2011 में राष्ट्रपति क्रिस्टीना डी किर्चनर की सरकार ने अमेरिकी डॉलर की खरीद पर प्रतिबंध लगाते हुए मुद्रा नियंत्रण की शुरुआत की थी, जो मुद्रास्फीति-प्रवण पेसो के बजाय बचत का पसंदीदा तरीका था। इसके परिणामस्वरूप काले बाजार में एक समानांतर विनिमय दर प्रचलित हो गई।

अर्जेंटीना ने विदेशों में रखी अपंजीकृत धनराशि पर आम माफी (एमनेस्टी) से, उम्मीद से लगभग छह गुना अधिक अर्थात् 116.8 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि को आकर्षित किया, जिससे राजकोषीय राजस्व में वृद्धि हुई जो दूसरी बार बजट घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकती है। माफी में प्रतिभागियों ने 31 दिसंबर से पहले अपने धन की घोषणा करने पर 10 प्रतिशत और उसके बाद 15 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान किया। उन्हें तीन वर्ष के सरकारी बांड में शून्य ब्याज पर या 1 प्रतिशत कूपन का भुगतान कर सात वर्ष के बांड का भुगतान करने का विकल्प दिया गया था। राष्ट्रपति मैक्री ने आम माफी की घोषणा की ताकि विदेशों में जमा 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक धन के अंश पर कब्जा करने में मदद मिल सके।⁴ अधिकांश धनराशि का उपयोग सरकारी मजदूरी और पेंशन का भुगतान करने के लिए किया जा रहा है।

उनका 'शून्य गरीबी' कार्यक्रम राष्ट्रपति मैक्री के एजेंडे में प्राथमिक बिंदुओं में से एक था। शासन का उद्देश्य गरीबी को कम करना रहा है, जबकि निकट भविष्य में शून्य गरीबी प्राप्त करने के लक्ष्य को खारिज कर दिया गया है। पारदर्शी सरकार के लिए उनकी बोली के समर्थन में, अर्जेंटीना सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी और जनगणना संस्थान ने तीन वर्ष के अंतराल के बाद, 2016 में गरीबी के आंकड़े जारी किए, जिसमें बताया गया कि अर्जेंटीना में गरीबों का सर्वेक्षण कुल 8.8 मिलियन लोगों या 32.2 प्रतिशत लोगों पर किया गया था। 31 शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया था।⁵ अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था के सुधार की प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही गरीबी के अधिक बढ़ने की संभावना है। मार्च 2016 में, सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषित किया कि अर्थव्यवस्था अब मंदी में नहीं है। आईएमएफ के अनुसार, 2017 में 2¼ प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने की आशा है, जो निजी खपत, मजबूत सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और निर्यात में तेजी से प्रेरित है।⁶ बहरहाल, देश को अभी भी कुछ समस्याओं को दूर करना है। उनमें से एक मुद्रास्फीति है। उच्च मुद्रास्फीति के कारण भोजन, पानी, आवास और पारगमन की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार कुछ उत्पादों पर सब्सिडी को कम कर रही है या रोक रही है, और बिजली और गैस की दरों में वृद्धि की है, पेसो का अवमूल्यन किया गया है, कुछ सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला किया गया है और अर्थव्यवस्था को गति देने और लंबे समय में मुद्रास्फीति को कम करने की अपनी बोली में शक्तिशाली ट्रेड यूनियनों के साथ मजदूरी तय करने में प्रवेश किया है।

राजनीतिक सुधार

विभिन्न सरकारी संगठनों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के अपने प्रयासों में, राष्ट्रपति मैक्री ने देश की सांख्यिकी एजेंसी में सुधार करने का आदेश दिया है। एजेंसी ने अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर सटीक डेटा प्रदान करने की अपनी विश्वसनीयता खो दी थी और 2013 में, अर्जेटीना आईएमएफ द्वारा गलत डेटा प्रकाशित करने वाला पहला देश बन गया। आशा की जाती है कि एजेंसी, अब स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, यह अर्जेटीना की अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास वापस लाने में सक्षम होगी। राष्ट्रपति मैक्री सरकारी अधिकारियों के कामकाज में बहुत आवश्यक पारदर्शिता लाने में सक्षम रहे हैं। डिक्री 201/2017⁷ सरकारी एजेंसियों और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तथा काबिना मंत्रियों और उनके करीबी रिश्तेदारों के बीच प्रोक्यूरेशन डेल टेसोरो मामलों पर केंद्रित है। डिक्री 202/20178 में सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक अधिकारियों के रिश्तेदारों और कार्यवाही के सख्त नियंत्रण के बीच की गई बोलियों के प्रचार या अनुबंध की आवश्यकता होती है। जून 2016 में राष्ट्रपति मैक्री ने चुनावी सुधार बिल की घोषणा की। कुछ मुख्य प्रस्तावित परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

—इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग: राजनीतिक दलों द्वारा मुद्रित और वितरित किए जाने वाले मौजूदा कागजी मतपत्रों को बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू की गई है। इस कदम के साथ, सरकार का इरादा वोट की गिनती के समय अधिक "पारदर्शिता और चपलता" हासिल करना है। चुनाव के दिन से पहले और बाद में विधेयक ऑडिट के प्रदर्शन को निर्धारित करता है।

—एकीकृत उम्मीदवार: यह उपाय देश में एक ही उम्मीदवार को विभिन्न श्रेणियों (जैसे राष्ट्रीय और प्रांतीय दौड़ में एक साथ चलने) में चुनाव लड़ने से रोककर चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।

—राष्ट्रपति की अनिवार्य बहस: विधेयक आम चुनावों में राष्ट्रपति पद के सभी उम्मीदवारों के लिए एक अनिवार्य टेलीविजन बहस का आयोजन करने और दूसरे दौर का मतदान (एक अपवाह आवश्यक होना चाहिए) के लिए कहता है।

—राजनीतिक दलों का वित्तपोषण: यह उपाय अर्जेटीना में वर्तमान चुनावी कानून को प्रभावी ढंग से संशोधित करता है, जिससे कानून के भ्रष्टाचार-विरोधी प्रावधानों को मजबूत करने के लिए कई उपकरण बनते हैं। सरकार का उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रतिबंधों में तेजी लाना और उनका विस्तार करना है। नेशनल इलेक्टोरल कोर्ट (सीएनई) में ऑडिटर्स बॉडी को आठ से 24 सदस्यों तक विस्तारित किया जाएगा - यह लंबे समय से चुनावी ऑडिटर्स की मांग रही है।⁹

—मध्यावधि चुनावों में उम्मीदवार सूची प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनमें 50% महिलाएं हैं। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए जहां पुरुष उम्मीदवार को शीर्ष पर पहुँच कर पदों का अनुपातहीन हिस्सा जीत सकते हैं, इसके अलावा, पुरुष और महिला नामों को प्रत्येक सूची की वरीयताओं की रैंकिंग में बदला जाना चाहिए। अर्जेटीना में पहले से ही कानून के लिए आवश्यक है कि कांग्रेस के सदस्यों में से कम से कम 30% सदस्य महिलाएं हैं (वर्तमान में चेंबर ऑफ डेप्युटी में 38.5% और सीनेट में 41.7% महिलाएं हैं)। नए कानून से अनुपात समानता की ओर बढ़ेगा।¹⁰

अर्जेटीना कांग्रेस के निचले सदन ने चुनावी सुधार विधेयक (जून 2016) को मंजूरी दे दी लेकिन सीनेट (नवंबर 2016) ने इसे खारिज कर दिया। सरकार ने कहा है कि वह सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें हासिल करने के लिए कांग्रेस के साथ काम करेगी।

समाज सुधार

उत्तरी प्रांतों को जोड़ने के लिए सरकार के बुनियादी ढांचा कार्यक्रम को धन जुटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। परियोजना का उद्देश्य अर्जेंटीना के 10 उत्तरी प्रांतों में जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार करना है, जिसका सीधा लाभ इन प्रांतों की 30% आबादी को मिलता है। मार्च 2017 में, विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईडीबीआर ऋण को मंजूरी दी।¹¹ आशा की जाती है कि अब उपलब्ध धन के साथ परियोजना को जल्दी लागू किया जा सकता है।

अर्जेंटीना में ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई में, सरकार ने इस क्षेत्र में अन्य देशों के उदाहरण का पालन करने का फैसला किया है, इसे केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि सुरक्षा का मुद्दा माना है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के एक फरमान के अंतर्गत सरकार ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है, जिससे सेना को देश भर में कई अनधिकृत हवाई क्षेत्रों से बाहर निकलने संदिग्ध ड्रग विमानों को मार गिराने की अनुमति मिल गई है, और नशीली दवाओं के संचालन में सैन्य भूमिका का विस्तार किया गया है। मानव अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा ड्रग्स नीति के सैन्यीकरण की आलोचना की गई है जो कहते हैं कि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा और अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं बढ़ जाएंगी। उन्हें लगता है कि इससे घरेलू नीतियों और पुलिस के अधिकार क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप होता है। वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि ड्रग/आपराधिक नेटवर्क उन नेटवर्क के निर्माण के लिए जनता, न्यायिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विकसित संबंधों के परिणामस्वरूप सफल होते हैं; और गरीब इलाकों में हिंसा का चक्र, युवाओं को इन समूहों में शामिल होने की अनुमति देता है। सरकार का ड्रग्स की समस्या को दूर करने के लिए एक व्यापक नीति बनाने में इन मुद्दों को शामिल करना आवश्यक है। न्यायपालिका के भीतर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की और अदालत की सुरक्षा निगरानी को बढ़ाया।

विदेश सम्बन्ध

पिछले वर्ष के दौरान, सरकार ने निवेश और व्यापार बढ़ाने की उम्मीद में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने पर सफलतापूर्वक ध्यान केंद्रित किया है। पिंक हाउस, व्हाइट हाउस के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में सक्षम रहा है। 2002 में अर्जेंटीना के 100 अरब के ऋण चूक से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। राष्ट्रपति मैक्री अप्रैल 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मिले। वे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध बनाने में सक्षम रहे। संयुक्त बयान में उल्लेख किया गया है कि दोनों देश नशीले पदार्थों की तस्करी, धन शोधन, आतंक के वित्तपोषण आदि से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। यह भी कहा गया कि दोनों राष्ट्र व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध थे।

नई सरकार डेढ़ वर्ष में, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र से परे, एशिया में चीन और जापान के साथ अर्जेंटीना के संबंधों को गहरा करने में सक्षम रही है, राष्ट्रपति मैक्री ने चीन की यात्रा की और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मेजबानी की। राष्ट्रपति मैक्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और चिली के राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट से भी भेंट की है।

देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को और बढ़ावा देने के लिए, इसने विश्व आर्थिक मंच के लैटिन अमेरिका शिखर सम्मेलन (अप्रैल 2017) की मेजबानी की। अर्जेंटीना 2018 में जी-20 शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा।

पहली बार आर्थिक शिखर सम्मेलन दक्षिण अमेरिका के किसी देश द्वारा आयोजित किया जाएगा। उसी वर्ष यह फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी भी करेगा। अर्जेंटीना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने की कोशिश कर रहा है।

इस क्षेत्र में, अर्जेटीना ने दिसंबर 2016 में मर्कोसुर की अध्यक्षता भी ग्रहण की। आशा की जाती है कि इसके नेतृत्व में यूरोपीय संघ-मर्कोसुर व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। अर्जेटीना महाद्वीप में निकट सहयोग बनाने के लिए प्रशांत गठबंधन की ओर भी देख रहा है। अर्जेटीना मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार नीतियों पर अलग-अलग विचारों को क्षेत्र को एकीकृत करने के एक अवसर के रूप में देखता है, क्योंकि मेक्सिको को संयुक्त राज्य अमेरिका से न मिलने वाले राजस्व के लिए दक्षिण की देखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसने, अपने नेतृत्व में मर्कोसुर क्षेत्रीय ब्लॉक से वेनेजुएला की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। सीएनएन की स्पैनिश भाषा सेवाओं (06 अप्रैल, 2017) को दिए एक साक्षात्कार में, राष्ट्रपति मैक्री ने कहा है कि, अगर वेनेजुएला की सरकार ने अपना व्यवहार नहीं बदला तो वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिकी व्यापार ब्लॉक मर्कोसुर से स्थायी रूप से निष्कासित किया जा सकता है।¹² अर्जेटीना के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार के आलोचक रहे हैं और उससे मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करने का आह्वान किया है। क्षेत्र में अर्जेटीना की ब्राजील जैसी अधिक स्वतंत्र भू-राजनीतिक भूमिका भी है, जो इस क्षेत्र का दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र है और अपनी अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने और राजनीतिक संकट को दूर करने की कोशिश करता है।

आगे की चुनौतियां

ब्यूनस आयर्स के महापौर होने के अपने राजनीतिक अनुभव का उपयोग कर , राष्ट्रपति मैक्री अर्जेटीना के लोगों का समर्थन पाना जारी रखने में सक्षम रहे हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और स्थिर विकास के बावजूद, अधिकांश लोग अब भी राष्ट्रपति को संदेह का लाभ दे रहे हैं। एक मुख्य बिंदु के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में श्री मैक्री के प्रदर्शन ने कठिन आर्थिक संदर्भ के बावजूद 55% के उच्च स्तर का अनुमोदन बनाए रखा है। ये दिसंबर 2016 में दैनिक ला नेसिआन के लिए पोलियारक्यूया कंसल्टर्स द्वारा आयोजित एक विशेष सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष हैं।¹³

फिलहाल, राष्ट्रपति मैक्री को अपने घरेलू एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अक्टूबर 2017 के मध्यावधि चुनावों के समय उनकी सरकार की नीतियों का परीक्षण होगा। चुनावों में अर्जेटीना कांग्रेस के चैंबर ऑफ डेप्युटी (लोअर हाउस) की 257 सीटों में से लगभग आधी का नवीनीकरण होगा। वर्तमान में, राष्ट्रपति मैक्री की पार्टी के पास चैंबर में केवल 42 सीटें हैं और अपने गठबंधन सहयोगियों के समर्थन से वे बहुमत बनाए रखने में सक्षम हैं। सीनेट (उच्च सदन) की 72 सीटों में से एक तिहाई के साथ ही प्रांतीय राज्यपालों के दो पदों के लिए भी चुनाव हैं। कैंबियोस गठबंधन और दो मुख्य विपक्षी समूह मुख्य दावेदार हैं: पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज (2007-15) का गठबंधन फ्रंट फॉर विक्टरी (एफपीवी), जो कांग्रेस में मैक्री का सबसे मजबूत विरोधी है और सर्जियो मस्सा के नेतृत्व में नवीकरणीय मोर्चा (एफआर) का गठबंधन, जो पेरोनिस्ट राजनीतिक आंदोलन का एक अधिक उदारवादी और सहकारी गुट माना जाता है। लगातार महंगाई और बेरोजगारी सरकार के लिए एक समस्या साबित हुई है , जिसके विरोध में शिक्षक और अन्य सरकारी कर्मचारी सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। वे वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं।¹⁴ सरकार को एक मध्य मार्ग खोजना होगा जिसके माध्यम से वह अपने सुधार एजेंडे की दिशा में काम कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि उसका कल्याणकारी खर्च पर्याप्त बना रहे।

चुनावों के परिणामों के बावजूद, राष्ट्रपति मैक्री को अर्जेटीना की स्थिर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास जारी रखना होगा। उनकी सरकार विदेशी निवेश के जरिए इसे हासिल करने की उम्मीद कर रही है। विदेशी निवेश का अभियान किर्चनर सरकार के अंतर्गत कई वर्षों के अलगाव के बाद , जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसी पश्चिमी शक्तियों के साथ संबंध टूट गए थे, दुनिया के साथ फिर से जुड़ने की एक व्यापक कोशिश का हिस्सा है।¹⁵

द्विपक्षीय संबंध

प्रमुख एशियाई देशों के साथ अर्जेंटीना के संबंधों में विविधता रही है, लेकिन हाल के वर्षों में ये समग्र रूप से बढ़ रहे हैं। इनमें से जापान और भारत सहित कुछ देशों और अर्जेंटीना के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी की शुरुआत से बने रहे हैं। भारत के साथ अर्जेंटीना के संबंध मामूली हैं, हालांकि वे बढ़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति और योग को अर्जेंटीना में हमेशा सराहा और सम्मान दिया जाता रहा है। ब्यूनस आयर्स में एक बहुत छोटा भारतीय समुदाय है।¹⁶ वर्तमान सरकार के अंतर्गत भारत अपनी दक्षिण-दक्षिण व्यस्तताओं को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र को, खासकर आर्थिक क्षेत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। भारत अपनी आर्थिक वृद्धि का विस्तार करने और अपने बढ़ते युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की कोशिश में, इस एलएसी क्षेत्र को अपनी सफलताओं में भागीदार बनाने की इच्छा रखता है।

भारत और एलएसी क्षेत्र के देश यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश होने की ऐतिहासिक कड़ी से अधिक साझा करते हैं, वे गरीबी में कमी, गुणवत्ता शिक्षा और सभी के लिए स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सामाजिक विकास की समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (जुलाई 2014) में भाग लेने के लिए अपनी ब्राजील यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने के लिए इस क्षेत्र के अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की।

भारत और अर्जेंटीना में सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में चीन में जी-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मौरिसियो मैक्री से भेंट की और परमाणु आपूर्तिकर्ता स मूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता का समर्थन करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। भारत और अर्जेंटीना ने 2009 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति मैक्री ने भारत से अर्जेंटीना में गैस भंडार की खोज में निवेश करने और पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए सहयोग का आह्वान किया है। भारत, दोनों देशों के बीच कृषि प्रौद्योगिकी, खनन और हाइड्रो कार्बन जैसे क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करने का इच्छुक है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों में विविधता ला रहा है और आज एलएसी क्षेत्र से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है। भारत और अर्जेंटीना अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान पर भी सहयोग करते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अर्जेंटीना के साथ, जलवायु परिवर्तन के परिणामों को समझने और उसे कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अक्षय ऊर्जा में निवेश करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जा रहा है।

संभावना है कि अर्जेंटीना (2018) में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान, संबंधों को और आगे बढ़ाया जाएगा। कृषि क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग के अलावा, भारत दवाइयों के व्यापार में वृद्धि के साथ इस क्षेत्र से अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को विकसित कर सकता है। 1995 में जी-15 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव की यात्रा के बाद बीस वर्षों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। जर्मनी के हैम्बर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन (2017) के मौके पर दोनों शासनाध्यक्षों ने द्विपक्षीय बैठक की। इन यात्राओं के अलावा, भारत और अर्जेंटीना के अधिकारी नियमित अंतराल पर एक दूसरे से मिलते रहे हैं, उदाहरण के लिए, 2013 में, भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने अर्जेंटीना का दौरा किया था। उसी वर्ष अर्जेंटीना के तत्कालीन विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज़ भी भारत आए थे।

भारत अब अर्जेंटीना और एलएसी क्षेत्र को जीवंत लोकतांत्रिक संस्कृति और बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं वाले राष्ट्रों के रूप में देखता है। इसी तरह, इस क्षेत्र में भारत के प्रति दृष्टिकोण में भी सकारात्मक बदलाव देखा गया है। भारतीय आईटी कंपनियों की सफलता, उच्च आर्थिक विकास, बड़े विदेशी अधिग्रहण का मतलब है कि अर्जेंटीना सहित इस क्षेत्र के देश निवेश और व्यापार के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। भारत के बढ़ते

अंतर्राष्ट्रीय पदचिह्न का अर्थ यह भी है कि भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने में एक साझेदार है। भारत और अर्जेंटीना के संबंध भविष्य में और बढ़ेंगे क्योंकि दोनों देशों की सरकारें यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अपने पारंपरिक साझेदारों से दूर व्यापार, सुरक्षा और राजनीतिक संबंधों के निर्माण के लिए एक सचेत प्रयास कर रही हैं।

**डॉ.स्तुति बनर्जी , भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली में अध्यक्षता हैं*

*

अस्वीकरण: व्यक्त मंतव्य लेखक के हैं और परिषद के मंतव्यों को परिलक्षित नहीं करते।

पादटिप्पणियां :

1 The Legislative Power of the Argentine Republic is vested in the National Congress. It consists of two Houses: the Senate and the House of Deputies. Senators represent each of the provincial states and the Federal Capital as autonomous political entities. They are chosen by their respective local Legislatures. The Deputies, on the other hand, represent the people and are directly chosen by them, their number depending on the number of inhabitants.

2 ----, "Argentina's Mid-Term Elections: Will Macri's Pro-Business Reforms Stand The Test?," <https://www.forbes.com/sites/riskmap/2017/03/23/argentinas-mid-term-elections-will-macris-pro-business-reforms-stand-the-test/#1b5ff11326ca>, 27 जून 2017 को अभिगम्य.

3 Daniel Bases, "Argentina, creditors agree to \$155 million more in default settlement: mediator," <http://www.reuters.com/article/us-argentina-debt-idUSKCNOWK1TK>, 27 जून 2017 को अभिगम्य.

4 Charlie Devereux, "Argentina Rakes in \$116.8 Billion From Hidden Assets Amnesty," <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-04/argentina-rakes-in-116-8-billion-from-hidden-assets-amnesty>, 28 जून 2017 को अभिगम्य.

5 Charlie Devereux, "Argentine Poverty Levels Show Size of Macri's Task," <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-28/argentine-poverty-levels-show-magnitude-of-macri-s-task>, 28 जून 2017 को अभिगम्य.

6 IMF, "Latin America and the Caribbean: Bouncing Back from Recession," <https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/05/18/NA190517Latin-America-and-the-Caribbean-Bouncing-Back-from-Recession>, 28 जून 2017 को अभिगम्य.

7 <https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/160467/20170322> पर उपलब्ध

8 <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=4119A19A19173FA1974C07BE9AC1B6EF?id=272923> पर उपलब्ध

9 ----, "Macri launches electoral reform bill," <http://www.buenosairesherald.com/article/216733/macri-finally-unveils-electoral-reform-bill>, 28 जून 2017 को अभिगम्य.

10 The Economist, “Lower house approves electoral reform bill,” <http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1734739957&Country=Argentina&topic=Politics&subtopic=Forecast&subsubtopic=Election+watch&u=1&pid=175624401&oid=175624401&uid=1>, 28 जून 2017 को अभिगम्य.

11 The World Bank, “Water Supply and Sanitation Development Program - Plan Belgrano,” <http://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2017/03/27/water-supply-sanitation-development-program-plan-belgrano>, 28 जून 2017 को अभिगम्य.

12 Reuters, “Argentina's Macri says Mercosur could permanently expel Venezuela,” <http://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-argentina-idUSKBN17902L>, 07 जुलाई 2017 को अभिगम्य.

13 La Nacio, “Dismiss evaluation of Macri's first year of management at Casa Rosada,” <http://www.lanacion.com.ar/1965964-dispar-evaluacion-del-primer-ano-de-gestion-de-macri-en-la-casa-rosada>, 28 जून 2017 को अभिगम्य.

14 Thomaz Favaro, “Argentina's Mid-Term Elections: Will Macri's Pro-Business Reforms Stand The Test?,” <https://www.forbes.com/sites/riskmap/2017/03/23/argentinas-mid-term-elections-will-macris-pro-business-reforms-stand-the-test/2/#4ae0f0c67b89>, 28 जून 2017 को अभिगम्य.

15 Benedict Mander, “Interview: Argentine president Mauricio Macri looks to end confrontational politics,” <https://www.ft.com/content/62219644-5807-11e6-9f70-badea1b336d4?mhq5j=e3>, 04 जुलाई 2017 को अभिगम्य.

16 Gonzalo S. Paz, “Argentina and Asia: China's Reemergence, Argentina's Recovery,” <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/UNCORRECTED%20PROOF-%20Paz.pdf>, 04 जुलाई 2017 को अभिगम्य.